LOK SABHA

Monday, March 28, 1966/Chaitra 7, 1888 (Saka)

The Lok Sabha met at two minutes past Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

Mr. Speaker: We are two minutes late

Shri Hem Barua: I think you should say something about this lack of quorum every day in the beginning.

Mr. Speaker: The House should be mindful of its dignity. It does not look nice that I should wait here and the House should start later than 11 O' Clock. I would request hon. Members that they should make it a point to be here by 11 O' Clock.

Shri Dwivedi.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

जवानों के परिवारों को सहायता

\+

*802. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा मोर्चों पर तैनात सैनिकों अथवा युद्ध में हताहतों के परिवारों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार तथा उनकी कठिनाईयों को यथासम्भव शीघ्र दूर करने तथा उनकी समस्याओं को हल करने के लिये क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कोई हिदायतें जारी की हैं ; और यदि हां, तो क्या ;

(ख) जो परिवार, अशिक्षित, अक्षम अथवा क्रियाशील न होने के कारण स्थानीय प्रशासन अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाते या असमर्थ होते हैं क्या उनकी खोज-खबर लेने की भी कोई व्यवस्था सोची गई है अथवा विचाराधीन है ;

(ग) क्या तहसील, जिला एवं अन्य प्रशासनिक इकाइयों के स्तर पर सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति उदार एवं सहानभूतिपूर्ण बर्ताव किये जाने हेतु सरकारी व्यवस्था में कोई सुधार किया जा रहा है ; और

(घ) क्या सुधार किया जा रहा है ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) Yes, Sir.

(b) The local authorities including Village Panchayats and Block Development Officers through their State Governments have been requested to look after the problems of such families.

(c) and (d). Yes, Sir. The welfare of the families of serving and ex-Service personnel is normally looked after by the DSS&ABs. However, to strengthen and assist this Organisation in its work, Government have sanctioned on long term basis the appointment of 4 Liaison Officers at the 4 Army Command Headquarters.

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है कि सोल्जर्स

और सेलर्स बोर्ड्स के होते हुए भी सोल्जर्स की शिकायतों को सुनने के लिए राज्य सरकारों द्वारा जिला और तहसील स्तर पर कार्रवाई नहीं होती ? यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई दूसरा परिपत्र हाल में लिखा है इस समय तक जिस के कारण राज्य सरकारें सोल्जर्स को और उनके फैमिनीज को हर प्रकार की सहायता दें ? अगर ऐसा सरकुलर सरकार ने भेजा है तो उसका क्या नतीजा हुआ और किन-किन राज्यों ने इस को स्वीकार किया है ?

Shri A. M. Thomas: As far as the Government of India is concerned, we attach considerable importance to the necessity for the welfare of families of soldiers, particularly jawans serving in the forward areas to be looked after. From time to time, we have been addressing the various State Governments in the matter. The Defence Minister has been himself writing letters to the Chief Ministers. The various State Governments have been also addressed in this matter. Letters have been written also to the Chief Secretaries, and we are quite conscious of the need for looking after their welfare, and everything possible is being done in this matter.

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि स्टेट्स ने क्या जवाब दिया ?

Mr. Speaker: Any reply received from the States?

Shri A. M. Thomas: The State governments' reaction has been quite favourable. In fact, as I have already stated, apart from that, there are other measures also taken to look after their welfare.

श्री म० ला० द्विवेदी : अभी मंत्री महोदय ने बतलाया कि सोल्जर्स सेलर्स बोर्ड के अलावा एक लियाजां आफिसर भी मुकर्रर किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सोल्जर्स और सेलर्स बोर्ड इनइफेक्टिव हैं या काम नहीं करते या राज्य सरकारें उनकी परवाह नहीं करतीं ? यदि ऐसा है तो सोल्जर्स सैलर्स बोर्डों को और मजबूत बनाने के लिए और वह कारगर हो सकें इस दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

Shri A. M. Thomas: Apart from the boards functioning, we have got other machinery also functioning. For example, I will refer to the three or four liaison officers attached to the various command headquarters.

Mr. Speaker: Anything done to make them more effective?

Shri A. M. Thomas: That would really have been found from the fact that even NCC officers have been entrusted with this work. They have met as many as 4754 families and it was known from the results that more than 95 per cent of the cases regarding the benefits to be given to these dependents and widows had all been settled and there may remain a few cases not yet settled and that would also be done so that their interests are looked after.

Shri P. C. Borooah: May I know whether the families of jawans include old and invalid parents also . . . and if so . . .

Shri A. M. Thomas: Yes, Sir.

Shri P. C. Borooah: . . has it come to the government's notice that quite a large number of these cases involve invalid parents who are still survivors and are their interests looked into?

Shri A. M. Thomas: Yes, Sir, their interests are also looked into.

Shri Bhagwat Jha Azad: Has the central government asked the states that they expect such kind of help as the minimum for the jawans because at present there are differences in the help and sympathy that they get in different states and that does not work well on the minds of jawans?

Shri A. M. Thomas: It is true that there is difference in the treatment that is being accorded; it varies

from state to state. But there is definitely a change in the attitude of the governments as well as the district officers regarding this matter about the welfare of the jawans' families. There is more consciousness among thes public at large and it is also reflected in the officers.

Shri Ranga: Why should there not be some uniformity?

Shri S. C. Samanta: May I know whether the district sailors and soldiers' board as it is at present constituted has only civilian authorities and if so are any enquiries made by them or through the district magistrates?

Shri A. M. Thomas: These boards have got their own machinery for enquiry. Apart from that there are welfare officers. Recently after the commencement of hostilities with Pakistan we have appointed some retired officers, majors and captains, released officers, to look after their welfare especially.

विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में हिन्दी

\+

*803. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश स्थित भारतीय दूतावासों को संविधान स्वीकृत राजभाषा हिन्दी में काम करने का आदेश दिया गया है ; और

(ख) क्या किसी भारतीय दूतावास में हिन्दी में काम आरम्भ हो गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) विदेश-स्थित हमारे मिशनों को सूचित कर दिया गया है कि 26 जनवरी, 1965 से, संविधान के अन्तर्गत, हिन्दी संघ की राजभाषा बन गई है और उसी तारीख से अंग्रेजी के साथ-साथ इसका उपयोग पत्र-व्यवहार करने के लिये किया जा सकता है और अगर कोई सरकारी कर्मचारी फाइलों पर नोट लिखने में इसका उपयोग करना चाहे तो कर सकता है ।

(ख) हमारे किसी भी मिशन ने अभी तक पूरी तरह से हिन्दी में काम करना शुरू नहीं किया है । लेकिन हमारे कुछ मिशन सीमित रूप में हिन्दी का उपयोग कर रहे हैं ।

श्री भागवत झा आजाद: मैं यह जानना चाहता हूं कि संसार के उन देशों में जहां पर हमारे पास वे देश अपनी भाषा में ही अपने नोट भेजते हैं, क्या हमने उन देशों को अपनी भाषा में नोट देना शुरू कर दिया है, या अभी अंग्रेजी में ही दे रहे हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : अभी तक हम नोट तो अंग्रेजी में दे रहे हैं मगर यह जब हमारे राजदूत नियुक्त होते हैं दूसरे देशों में तो उन का जो वारेंट आफ एपायंटमेंट होता है वह हिन्दी में होता है और मैं उन पर हिन्दी में दस्तखत करता हूं ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं जानना चाहता हूं कि आपने उन के पास यह लिखित भेजा कि अमुक इस वर्ष से हिन्दी हमारी राजभाषा हुई क्या इसके साथ आपने उन को यह भी निर्देश दिया है कि कम से कम आप उनसे कुछ विषयों पर हिन्दी में कार्य करने की आशा रखते हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : अभी तक ऐसा मैं नहीं कर पाया हूं ।